भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-93
उत्तर देने की तारीख-29/07/2024

समग्र शिक्षा अभियान के तहत ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड

†***93. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्यालयों में शिक्षण अनुभव को बढ़ाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यान्वित की गई डिजिटल पहल, विशेषकर ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या डिजिटल पहल, विशेष रूप से ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड विद्यालयों में प्रौद्योगिकी-समर्थित शिक्षण वातावरण के सृजन में योगदान देती है और यदि हां, तो इसका छात्रों के समग्र शैक्षिक अनुभवों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

माननीय संसद सदस्य श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के तहत ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 93 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु 20 फरवरी, 2019 को ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (ओडीबी) शुरू किया गया था। डिजिटल बोर्ड स्कूलों में कक्षा 9वीं से शुरू किए गए थे, जिसका उद्देश्य एक शिक्षण-कक्ष को डिजिटल शिक्षण-कक्ष में बदलना और छात्रों को किसी भी समय और किसी भी स्थान पर ई-संसाधन उपलब्ध कराना था। स्मार्ट शिक्षण-कक्ष तत्व के रूप में ओडीबी को "समग्र शिक्षा" योजना के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) घटक के तहत जोड़ा गया था, जो कि 2018-19 से प्रभावी स्कूली शिक्षा के लिए एक केंद्र प्रायोजित एकीकृत योजना है। ओडीबी अब समग्र शिक्षा के आईसीटी घटक का हिस्सा है। स्कूली शिक्षा में आईसीटी और स्मार्ट शिक्षण-कक्षों की पहल में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार की काफी क्षमता है। समग्र शिक्षा के आईसीटी और डिजिटल पहल घटक में कक्षा VI से XII तक के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं।

आईसीटी और स्मार्ट शिक्षण-कक्ष घटक के तहत स्कूलों में डिजिटल बोर्ड और आईसीटी लैब का उपयोग करके स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 'आईसीटी और डिजिटल पहल' के तहत गैर-आवर्ती/आवर्ती अनुदान निम्नलिखित दो विकल्पों के रूप में उपलब्ध है:

(i) **विकल्प I:** इस विकल्प के तहत जिन स्कूलों ने पहले आईसीटी सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, वे अपनी मांग और आवश्यकता के अनुसार आईसीटी या स्मार्ट शिक्षण-कक्ष का विकल्प चुन सकते हैं। 700 से अधिक नामांकन के मामले में, एक अतिरिक्त आईसीटी लैब पर भी विचार किया जा सकता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के पास टैबलेट/लैपटॉप/नोटबुक/एकीकृत शिक्षण अधिगम उपकरण और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ-साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण और संसाधन सहायता जैसे हार्डवेयर खरीदने के लिए लचीलापन है। इसमें स्वीकृत स्कूलों की संख्या के अनुपात के आधार पर डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम और डीटीएच चैनलों के लिए सहायता शामिल होगी।

(ii) **विकल्प II:** इस विकल्प के तहत जिन स्कूलों ने पहले ही आईसीटी सुविधा का लाभ उठाया है, वे योजना के मानदंडों के अनुसार स्मार्ट शिक्षण-कक्ष/टैबलेट का लाभ उठा सकते हैं।

वित्तीय प्रावधान:

- **आईसीटी लैब:** 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति विद्यालय 6.40 लाख रुपये तक का गैर-आवर्ती अनुदान और प्रति विद्यालय प्रति वर्ष 2.40 लाख रुपये तक का आवर्ती अनुदान। वर्ष 2023-24 से, यह योजना विद्यालय नामांकन के आधार पर चरणबद्ध

तरीके से वित्तपोषण भी प्रदान करती है। (संख्या < 100: 2.5 लाख रुपये, 100-250 के बीच की संख्या: 4.5 लाख रुपये, 250-700 के बीच की संख्या: 6.4 लाख रुपये)

- **स्मार्ट शिक्षण-कक्ष:** स्मार्ट शिक्षण-कक्ष (प्रति विद्यालय 2 स्मार्ट शिक्षण-कक्ष) के लिए गैर-आवर्ती अनुदान 2.40 लाख रुपये है और आवर्ती अनुदान 38,000 रुपये (ई कंटेंट और डिजिटल संसाधन, बिजली के लिए शुल्क सहित) है। दिनांक 19 जुलाई, 2024 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 1,39,181 आईसीटी प्रयोगशालाओं और 1,26,881 स्मार्ट शिक्षण-कक्षों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के अनुसार, प्रौद्योगिकी पहलों का मुख्य कार्य शिक्षण-अधिगम और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सुधार करना, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करना, शिक्षक तैयारी और व्यावसायिक विकास में सहायता करना, दिव्यांगों तक शैक्षिक पहुंच को बढ़ाना और प्रवेश, उपस्थिति, मूल्यांकन आदि से संबंधित प्रक्रियाओं सहित शैक्षिक नियोजन, प्रबंधन और प्रशासन को सुव्यवस्थित करना होगा (एनईपी 2020, प्रौद्योगिकी उपयोग और एकीकरण)।

एनईपी 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल मौजूद है जो शिक्षा तक मल्टी-मोड पहुँच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। इससे देश भर में लगभग 25 करोड़ स्कूली बच्चे लाभान्वित होंगे। इस पहल के प्रमुख घटक हैं दीक्षा - देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा, कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए 200 पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनल, डिजिटल पुस्तकों और ई-सामग्री का प्रसार करने के लिए ई-पाठशाला पहल, ई-जादुई पिटारा एक डिजिटल ऐप है जो भौतिक जादू पिटारा का पूरक है, दीक्षा मंच पर निर्मित वर्चुअल लैब्स पर एक वर्टिकल जहां कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विषयों के लिए विज्ञान और गणित के 280 वर्चुअल लैब उपलब्ध कराए गए हैं।

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की उपरोक्त डिजिटल पहल, विशेष रूप से "आईसीटी और स्मार्ट शिक्षण-कक्ष घटक" छात्रों को बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और कक्षा को तकनीक-संचालित कक्षा में बदल देते हैं। छात्र संसाधनों की व्यापक पहुंच का लाभ उठाते हुए मल्टीमीडिया सामग्री और इंटरैक्टिव गतिविधियों के साथ जुड़ाव बढ़ाते हैं। यह छात्रों के लिए गहरी समझ, सहयोग और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है, जिससे उनका समग्र शैक्षिक अनुभव समृद्ध होता है।

****